माननीय न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल तथा जसपाल सिंह के समक्ष

सुमेश कुमार गुप्ता—अपीलकर्ता

बनाम

सपना गुप्ता —उत्तरदाता

2013 का एफएओ नंबर 980

जुलाई 10,2013

परिवार कला अधिनियम, 1984 - धारा 19 - हिन्द विवाह अधिनियम, 1955 - धारा 13 बी, 28 (1976 में संशोधित) - अपील - केवल दो मामलों में बनाए रखने योग्य - एक निर्णय के खिलाफ बनाए रखने योग्य - एक आदेश के खिलाफ भी, यदि वह आदेश एक वादकालीन आदेश नहीं है - धारा 13-बी के तहत याचिका खारिज कर दी गई, क्योंकि प्रतिवादी-पत्नी दूसरे प्रस्ताव के चरण में आपसी सहमति से विवाह के विघटन के लिए सहमत नहीं थी - फैमिली कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ अंत में फैसला किया याचिका और एचएमए अधिनियम की धारा 13 बी के तहत तलाक देने से इनकार - परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के तहत एक अपील बनाए रखने योग्य होगी।

अभिनिर्धारित किया गया है कि 1984 के अधिनियम का अध्याय V अपील और संशोधन से संबंधित है। इस अध्याय में केवल एक खंड अर्थात् धारा 19 है। धारा 19 की उपधाराएं (1), (2), (3) और (6) अपील से संबंधित हैं। धारा 19 की उपधारा (4) में पुनरीक्षण का प्रावधान है। धारा 19 की उपधारा (5) अपील और पुनरीक्षण दोनों से संबंधित है। 1984 के अधिनियम की धारा 19 को पढ़ने से पता चलता है कि उप-धारा (1) के तहत, उप-धारा (2) में प्रदान किए गए को छोड़कर, परिवार न्यायालय के प्रत्येक निर्णय या आदेश से उच्च न्यायालय में अपील की जाती है, तथ्यों और कानून दोनों पर। यह सीआई विल प्रक्रिया संहिता, 1908, दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में, "सीआरपीसी") या किसी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज के बावजूद है। हालांकि, एक वादकालीन आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं है। धारा 19 की उपधारा (2) विशेष रूप से पक्षकारों की सहमति से कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश या सीआरपीसी के अध्याय IX के तहत पारित आदेश से किसी अपील को प्रतिबंधित करती है। धारा 19 की उपधारा (4) दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय IX के तहत पारित आदेश के संबंध में पुनरीक्षण शक्ति प्रदान करती है, जो कि प्रकृति में एक वार्ताकार आदेश नहीं। धारा 19 की उपधारा (5) कुटुम्ब न्यायालय

के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री से किसी अपील या पुनरीक्षण का स्पष्ट रूप से प्रतिषेध करती है, सिवाय इसके कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन यथा उपबंधित है।

(पैरा 10)

आगे कहा गया कि धारा 19(1) में एक गैर-बाधा खंड भी है, जिसमें कहा गया है कि ".... सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), या किसी अन्य कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी गैर-बाधा खंड यह भी स्पष्ट करता है कि अधिनियम की धारा 28 में निहित प्रावधान वर्तमान पीयू के लिए प्रासंगिक नहीं होगा। 1984 अधिनियम की धारा 19 (1) के अवलोकन से पता चलता है कि एक अपील केवल दो मामलों में सुनवाई योग्य है। सबसे पहले, यह एक निर्णय के खिलाफ बनाए रखने योग्य है। दूसरे, यह एक आदेश के विरुद्ध भी बनाए रखने योग्य है, मैं यह आदेश एक वादकालीन आदेश नहीं है।

(पैरा 11)

आगे कहा गया कि उपरोक्त से, यह उभरेगा कि फैमिली कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ अंततः याचिका का फैसला करना और अधिनियम की धारा 13 बी के तहत तलाक देने से इनकार करना, 1984 अधिनियम की धारा 19 के तहत एक अपील बनाए रखने योग्य होगी क्योंकि आदेश उक्त अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के तहत आता है।

(पैरा 12)

अपीलकर्ता के वकील *विनोद एस. भारद्वाज।*

न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल

(1) पति की यह अपील हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 13 बी के तहत पारित दिनांक 24.7.2012 के एक आदेश को चुनौती देती है, जिसके तहत आपसी सहमति से तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन की याचिका खारिज कर दी गई थी।

(2) अपीलकर्ता-पति का मामला, जैसा कि तत्काल अपील में सामने रखा गया है, यह है कि पक्षों के बीच विवाह 11.6.1989 को जबलपुर (मध्य प्रदेश) में हिंदू संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार संपन्न हुआ था। में स

उक्त विवाह के फलस्वरूप दो बच्चों श्रुति गुप्ता की आयु लगभग 21 वर्ष और समर्थ गुप्ता की आयु लगभग 15 वर्ष थी। अपने स्वभाव के लिए ड्यूक डि (टेरेंस), पार्टियों ने आपसी सहमति से शादी को भंग करने का फैसला किया। 'उन्होंने एक समझौता किया और समझौते के अनुसार, अपीलकर्ता-पति को अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के रखरखाव के लिए प्रतिवादी-पत्नी को गुजारा भत्ता के लिए पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में 1.80 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा। पक्षकारों के बीच हुए समझौते को देखते हुए, अधिनियम की धारा 1313 के तहत आपसी सहमति से पक्षों के बीच विवाह के विघटन के लिए एक संयुक्त याचिका दायर की गई थी, इसके अलावा, अधिनियम की धारा 1313 के तहत यथा अपेक्षित प्रतिवादी-पत्नी का पहला प्रस्ताव बयान दर्ज किया गया था। 16.4.2012 को, प्रतिवादी-पत्नी ने विघटन ओ ('आपसी सहमति से विवाह' के लिए सहमति नहीं दी और दूसरे प्रस्ताव के बयान को दर्ज करने के लिए समय के लिए प्रार्थना की और समय-समय पर आराम को स्थगित कर दिया गया। तदनुसार, प्रतिवादी-पत्नी ने इस आशय का बयान दिया कि वह नहीं चाहती थी कि याचिकाकर्ता के साथ उसका विवाह आपसी सहमति से तलाक की डिक्री द्वारा भंग किया जाए, पति द्वारा दायर अधिनियम की धारा 1313 के तहत याचिका को फैमिली कोर्ट, गुड़गांव विडीसी आदेश दिनांक 24.7.2012 द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसलिए, वर्तमान अपील।

(3) इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.3.2013 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने यह स्थापित करने में समय लिया था कि वर्तमान अपील अधिनियम के तहत सुनवाई योग्य थी।

(4) अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों ने वैवाहिक विवाद से समझौता किया है और इसके संदर्भ में, प्रतिवादी-पत्नी को 1.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। यह उस आधार पर था कि प्रतिवादी-पत्नी ने अधिनियम की धारा 1313 के तहत पहले प्रस्ताव पर एक बयान दिया था। हालांकि, उपरोक्त राशि प्राप्त करने के बाद, वह अपनी पूर्व सहमति से मुकर गई और अधिनियम की धारा 1313 के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए सहमत नहीं हुई। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई थी। अनिल कुमार जैन बनाम ***मयू जैन*** (1) में 1 अप्रैल शीर्ष अदालत के फैसले और अनिल ***खटवानी बनाम*** निष्ठा खटवानी (2) ***में राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले*** से समर्थन प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिका फैमिली कोर्ट के समक्ष दायर की गई थी और फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 (संक्षिप्तता के लिए) की धारा 19 के तहत अपील सुनवाई योग्य थी। "1984 अधिनियम")।

(7) एआईआर 2010 एससी 229

(2) एआईआर 2012 सीसी 2125

(5) अपीलकर्ता के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिली। इस अपील में विचार के लिए उठने वाले मुद्दे को अंडसीआर के रूप में विभाजित किया जा सकता है: -

(a) अधिनियम की धारा 28 के तहत अपील का दायरा;

(b) क्या अधिनियम की धारा 13 बी के तहत दायर याचिका को खारिज करने के संबंध में परिवार न्यायालय के निर्णय या आदेश के खिलाफ 1984 अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील सुनवाई योग्य होगी;

(c) क्या तथ्यों और परिस्थितियों में, फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 13 बी के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज करने में त्रुटि में था।

(6) पहला अंक ले रहा है। अधिनियम की धारा 28 को स्कैन किया जा सकता है, मूल असंशोधित धारा 28 में सभी डिक्री के साथ-साथ अधिनियम में विशेष रूप से उल्लिखित आदेशों के खिलाफ अपील का प्रावधान किया गया है, केवल लागत के विषय को छोड़कर। असंशोधित धारा 28 इस प्रकार है: -

"28. डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन और अपील, - इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा की गई सभी डिक्रियां और आदेश उसी रीति से बलित किए जाएंगे जैसे न्यायालय की उसके मूल सिविल अधिकारिता के प्रयोग में की गई डिक्री और आदेश प्रवृत्त होते हैं और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपील की जा सकेगी: बशर्ते कि केवल लागत के विषय पर कोई अपील नहीं होगी, "

(7) अधिनियम की धारा 28 में 1976 के अधिनियम 68 द्वारा संशोधन किया गया जिसे 27.5.1976 से प्रभावी बनाया गया। 1976 में अधिनियम के एक महान संशोधन की धारा 28 इस प्रकार है: -

(1) **का उपयोग कर सकते हैं डिक्री और आदेशों** से अपील- (l) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा की गई सभी डिक्री, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मूल सिविल अधिकारिता में किए गए न्यायालय की डिक्री के रूप में अपील योग्य होंगी और ऐसी प्रत्येक अपील उस न्यायालय में होगी जिसके लिए अपील सामान्यतः अपने मूल सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दिए गए न्यायालय के निर्णयों से की जाती है।

(2) धारा 25 या धारा 26 के अधीन इस अधिनियम की किसी प्रक्रिया में न्यायालय द्वारा किए गए आदेश, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपील योग्य होंगे यदि वे अंतरिम आदेश

नहीं हैं, और ऐसे प्रत्येक आदेश

अपील उस न्यायालय में होगी जिसके लिए अपील आमतौर पर अपने मूल नागरिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिए गए न्यायालय के निर्णयों से होती है।

(3) केवल लागत के विषय पर इस धारा के तहत कोई अपील नहीं होगी

(4) इस धारा के तहत प्रत्येक अपील डीसीसीआरसीसी या आदेश की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर की जाएगी।

(8) अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के तहत, सभी डिक्री से अपील की जाती है। धारा 28 की उपधारा (2) के तहत, अधिनियम की धारा 25 और 26 के तहत पारित आदेशों के खिलाफ अपील सुनवाई योग्य है- हालांकि, केवल उपधारा (3) के मद्देनजर लागत के विषय पर कोई अपील सक्षम नहीं है। उप धारा (4) अपील दायर करने के लिए डिक्री या आदेश की तारीख से नब्बे दिनों की सीमा निर्धारित करती है। संशोधन द्वारा लाया गया एक बुनियादी अंतर यह है कि जबकि पहले अधिनियम की धारा 28 में डिक्री और आदेशों से अपील का प्रावधान था, जबकि संशोधन के बाद अपील केवल डिक्री से प्रदान की जाती है।

(9) दूसरे बिंदु पर ध्यान देते हुए, 1984 के अधिनियम की धारा 19 को पुन: प्रस्तुत करना उचित होगा जो इस प्रकार है: -

"19. अपील। (1) उपधारा (2) में यथा उपबंधित के सिवाय, और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी। 1973 (1974 का 2), या किसी अन्य कानून में, एक अपील हर निर्णय या आदेश से झूठ होगी, तथ्यों और कानून दोनों पर। ligh न्यायालय के लिए एक परिवार न्यायालय के एक मध्यस्थ आदेश नहीं होने के नाते.

(2) पक्षकारों की सहमति से कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश से या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय IX के अधीन पारित आदेश से कोई अपील नहीं होगी: परन्तु इस उपधारा की कोई बात उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी अपील या दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय IX के अधीन पारित किसी आदेश को लागू नहीं होगी, (i) कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारंभ होने से पूर्व, 1973 (1974 का 2) के संबंध में।

(3) इस धारा के तहत प्रत्येक अपील को परिवार न्यायालय के निर्णय या आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) उच्च न्यायालय, अपने स्वयं के प्रस्ताव से या अन्यथा, किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड के लिए कॉल कर सकता है और उसकी जांच कर सकता है जिसमें कुटुम्ब न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित है, इस उद्देश्य के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय में एक आदेश पारित किया है ('आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के रूप में खुद को संतुष्ट करना, एक वार्ताकार आदेश नहीं है, और इस तरह की कार्यवाही की नियमितता के रूप में.

(5) पूर्वोक्त को छोड़कर, परिवार न्यायालय के किसी भी निर्णय, आदेश या डिक्री से किसी भी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट अपील की सुनवाई एक पीठ द्वारा की जाएगी जिसमें दो या अधिक न्यायाधीश होंगे।

(10) 1984 के अधिनियम का अध्याय V अपील और पुनरीक्षण से संबंधित है। इस अध्याय में केवल एक खंड अर्थात् धारा 19 है। धारा 19 की उपधाराएं (1), (2), (3) और (6) अपील से संबंधित हैं। धारा 19 की उपधारा (4) में पुनरीक्षण का प्रावधान है। धारा 19 की उपधारा (5) अपील और पुनरीक्षण दोनों से संबंधित है। धारा 1984 अधिनियम के पढ़ने से पता चलता है कि उप-धारा (1) के तहत, उप-धारा (2) में प्रदान किए गए को छोड़कर, परिवार न्यायालय के प्रत्येक निर्णय या आदेश से उच्च न्यायालय में अपील की जाती है, दोनों तथ्यों और कानून पर। यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में, "सीआरपीसी") या किसी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज के बावजूद है। हालांकि, एक वादकालीन आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं है। धारा 19 की उपधारा (2) विशेष रूप से पक्षकारों की सहमति से कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश या सीआरपीसी के अध्याय IX के तहत पारित आदेश से किसी अपील को प्रतिबंधित करती है। धारा 19 की उप-धारा (4) सीआरपीसी के अध्याय IX के तहत पारित आदेश के संबंध में पुनरीक्षण शक्ति प्रदान करती है, जो प्रकृति में एक वादकालीन आदेश नहीं है। धारा 19 की उपधारा (5) कुटुम्ब न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री से किसी अपील या पुनरीक्षण का स्पष्ट रूप से प्रतिषेध करती है, सिवाय इसके कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) से उपबंधित है। धारा 19 की उपधारा (6) यह निर्धारित करती है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की सुनवाई उक्त की धारा 19 की उपधारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक निर्णय से दो या अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी है ढोंग।

(11) धारा 19(1) में एक गैर-अवलोकन खंड भी है, जिसमें कहा गया है11.... सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), या किसी अन्य कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी...। गैर-बाधा खंड यह भी स्पष्ट करता है कि अधिनियम की धारा 28 में

निहित प्रावधान वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं होगा। 1984 अधिनियम की धारा 19 (1) के अवलोकन से पता चलता है कि एक अपील केवल दो आसान में बनाए रखने योग्य है। सबसे पहले, यह एक निर्णय के खिलाफ बनाए रखने योग्य है। दूसरे, यह एक आदेश के खिलाफ भी बनाए रखने योग्य है, अगर वह आदेश एक वादकालीन आदेश नहीं है।

(12) उपर्युक्त से यह उभर कर सामने आएगा कि फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध याचिका पर अंतिम रूप से निर्णय लेने और अधिनियम की धारा 13ख के तहत तलाक देने से इनकार करने के बाद, 1984 के अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील सुनवाई योग्य होगी क्योंकि यह आदेश उक्त अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है।

(13) विवाद के गुण-दोष से संबंधित अपील के अंतिम चरण की जांच करते हुए, अनिवार्य रूप से अधिनियम की धारा 13 बी का संदर्भ दिया जाना चाहिए। यह इस प्रकार पढ़ता है: -

> **"13ख. आपसी सहमति से तलाक-**(l) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विवाह-विवाह, दोनों पक्षों द्वारा एक साथ विवाह करने के लिए संशय के विघटन की याचिका जिला न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकेगी, चाहे ऐसा विवाह मुख्य आयु विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976, (1976 का 68) के प्रारंभ होने से पहले या बाद में इस आधार पर अनुष्ठापित किया गया हो कि वे एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि से अलग-अलग रह रहे हैं, कि वे एक साथ नहीं रह पाए हैं और वे पारस्परिक रूप से सहमत हुए हैं कि विवाह को भंग कर दिया जाना चाहिए।

(2) उपधारा (l) में निर्दिष्ट याचिका की प्रस्तुति की तारीख के छह महीने से पहले और उक्त तारीख के अठारह महीने बाद नहीं किए गए दोनों पक्षों के प्रस्ताव पर, यदि याचिका इस बीच वापस नहीं ली जाती है, तो अदालत पक्षकारों को सुनने के बाद और ऐसी जांच करने के बाद, जैसा वह ठीक समझे, संतुष्ट होने पर, फेड किया जाएगा, कि एक विवाह संपन्न हो गया है और याचिका में कथन सत्य हैं, डिक्री की तारीख से विवाह को ई फ्लीट के साथ भंग करने की घोषणा करते हुए तलाक की डिक्री पारित करें। (मैं4) उप-धारा (l) के एक सादे पठन से पता चलता है कि विवाह के पक्षकार जहां भी आपसी सहमति से सहमत होते हैं कि विवाह को तलाक की डिक्री द्वारा इस आधार पर भंग कर दिया जाना चाहिए कि वे जीवित हैं

एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए अलग-अलग, दोनों पक्ष जिला न्यायालय में तलाक के लिए याचिका पेश कर सकते हैं। ऐसी याचिका प्रस्तुत किए जाने पर प्रथम प्रस्ताव के माध्यम से बयान अभिलिखित किया जाएगा। उप-धारा (2) के तहत, दूसरा प्रस्ताव करना आवश्यक होगा जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट याचिका की प्रस्तुति की तारीख से छह महीने के बाद और पहले प्रस्ताव की तारीख से अठारह महीने के बाद नहीं होना चाहिए जहां याचिका वापस नहीं ली गई है। पक्षकारों की सुनवाई के बाद संतुष्ट

होने पर न्यायालय डिक्री की तारीख से तलाक की डिक्री पारित करता है।

(15) वर्तमान सहजता में, पत्नी ने दूसरी बार निम्नलिखित कथन किया: -

उन्होंने कहा, 'मैं आईएमए के तहत आपसी सहमति से तलाक नहीं चाहता। फ्लिक वर्तमान याचिका खारिज की जा सकती है।

(16) इस प्रकार, दूसरा बयान अधिनियम की धारा 13 बी की आवश्यकता के अनुरूप और सहमति में नहीं है और इसलिए, आपसी सहमति से तलाक के लिए कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। पत्नी के दूसरे प्रस्ताव पर बयान की आवश्यकता के पूर्ण विवरण में, अधिनियम की धारा 13 बी के तहत याचिका को खारिज करने में नीचे के न्यायालय को उचित ठहराया गया था।

(17) यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि अनिल कुमार में अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया **था। इयान का मामला (सुप्रा)** वह था जहां honble apex कोर्ट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 ने पार्टियों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए तलाक की अनुमति दी थी। अनिल खटवानी के मामले (सुप्रा) में राजस्थान **प्रथम लीग कोर्ट** का निर्णय भी उसमें शामिल व्यक्तिगत तथ्य स्थिति पर आधारित था। इसलिए, ये निर्णय अपीलकर्ता की आसानी में मदद या अग्रिम नहीं करते हैं।

(18) उपरोक्त के मद्देनजर, इस अपील में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

(19) अपील को सीमा द्वारा रोक दिया गया है और अपील दायर करने में 187 दिनों की देरी के लिए माफी के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। चूंकि अपील गुणावगुण के आधार पर खारिज कर दी गई है, इसलिए विलंब के लिए क्षमा हेतु आवेदन में आगे कोई आदेश पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है और उसका निपटान भी किया जाता है।

*****

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है, ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मीनू वर्मा,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा